strengthen cooperation in combating illegal trafficking in narcotics at all levels, including production, trafficking and drug abuse.

विदेश में भारतीय मिशन द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

1841. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों के लिये एकसमान पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, यदि हां, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और उसका आधार क्या है;

(ग) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 1997 के "पायानियर" में "संपादक के नाम पत्र" कॉलम में प्रधान मंत्री के नाम संबोधित पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सउदी अरब में संचालित स्कूलों में प्रिंसिपल सहित अन्य पदों का मुस्लिम के लिये आरक्षण तथा इन स्कूलों में प्रातःकालीन सभा का आरंभ पवित्र कुरान के पाठ के साथ करने का क्या औचित्य है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) केवल इथियोपिया, चीन, तंजानिया, बंगलादेश, यमन और ईरान में विदेश स्थित भारतीय राजदूतावास स्कूल चला रहे हैं।

(ख) यह स्कूल सी०बी०एस०ई० या आई०सी०एस०ई० से संबद्ध हैं तथा उनके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। बीजिंग में स्कूल अनौपचारिक रूप से राजदूतावास के कर्मचारियों की पत्नियों और स्थानीय भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। यह केवल चौथी कक्षा तक चलाया जा रहा है, जिसमें कड़ाई से किसी पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) इस समय सउदी अरब में स्थित भारतीय मिशन कोई स्कूल नहीं चला रहा है। सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्कूल सऊदी शिक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं और उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। इन स्कूलों में प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के पद केवल मुस्लिमों के लिए ही आरक्षित नहीं हैं। इन स्कूलों में पवित्र कुरान की आयतों का सस्वर पाठ स्थानीय प्रथाओं के अनुसरण में किया जाता है।

Transportation to North-Eastern states through Bangladesh

1842. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any initiative to facilitate transportation and communication through Bangladesh to connect North-Eastern States to the mainland of India;

(b) if so, the details thereof and the response of Bangladesh thereto; and

(c) the steps taken/proposed to be taken to materialise this long standing demand of North-Eastern States?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) to (c) The question of transit facilities through Bangladesh to provide transportation link between the North-eastern States of India and the mainland has been raised on many occasions with the Government of Bangladesh. The subject remains under discussion between the two Governments.

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता

1843. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पड़ोसी देशों के साथ कौन-कौन से मुद्दे लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सभी मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य से भारत और अन्य पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गति में तेजी पाने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो मुद्दे-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और अन्य पड़ोसी देशों के बीच

वार्ता शुरू हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (ङ) पड़ोसी देशों के साथ देश-वार अनिर्णित मसले नीचे दिए गए हैं:—

नेपाल

पंचेश्वर परियोजना

नेपाल और भारत संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसे फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सम्पन्न हुई महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित संधि के लागू होने की तारीख से 6 माह के भीतर अन्तिम रूप दिया जाना है। नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ संधि में निर्दिष्ट विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन पर बातचीत चल रही है जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तेजी से अन्तिम रूप दिया जाना शामिल है।

सुरक्षा मामले

सरकार सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए हैं। सरकार नेपाल में भारत के विरूद्ध चलाई जा रही आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में प्राप्त रिपोर्टों पर चिन्तित है। नेपाल की सरकार का रवैया सहयोगी रहा है और भारत-नेपाल की खुली सीमा पर अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें हतोत्साहित करने के बारे में सिफारिशें करने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक शीघ्र होने की संभावना है।

भारतीय अध्यापक

नेपाल में भारतीय अध्यापकों जिन्हें अभी तक स्थायी होने का दर्जा नहीं दिया गया है, के प्रश्न को अनेक अवसरों पर नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया जाता रहा है जिसमें काठमांडू स्थित हमारे राजदूत के साथ-साथ विदेश मंत्री डा. पी.सी. लोहानी की अगस्त, 1996 में हुई भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत शामिल है। नेपाल के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि परस्पर संतुष्टि के लिए इसे शीघ्र ही निपटा लिया जाएगा।

श्रीलंका

भारतीय मछुआरे

विदेश मंत्री ने श्रीलंका की अपनी हाल की यात्रा के दौरान पाक स्ट्रेट्स में भारतीय मछुआरों को आ रही समस्याओं पर श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की थी और उनके विरूद्ध हिंसा की घटनाओं पर भारत की गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हालांकि दोनों पक्ष एक-दूसरे की सीमा में अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता और अनुकम्पा तथा समझबूझ की भावना के साथ समस्याओं का हल निकालने के लिए सहमत हुए तथापि यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने टूटीकोरिन और कोलम्बो के बीच चल रही नौकाओं के चालकों को आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान को खोजने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्रीलंका के प्राधिकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें उपयुक्त समाधान ढूंढ निकालने के विचार से बातचीत करने के लिए टूटीकोरिन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

2. मछुआरों के मसले पर और बातचीत फरवरी, 1997 में श्रीलंका के शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान हुई और दोनों पक्ष मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पार राह भटके मछुआरों के मामलों से निपटने के लिए रूपात्मकताओं पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं।

म्यामां

सीमांकन

भारत-म्यामां-बंगलादेश के त्रि-सन्धि स्थल से आरंभ होने वाली 906 मील लम्बी सीमा के सीमांकन का कार्य अक्तूबर, 1968 में शुरू हुआ था। सीमांकन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य अभी अधूरा है:—

(I) हुर्दुगन दर्रे के उत्तर से उत्तरी त्रि-संधि स्थल (भारत-चीन-म्यामां) तक लगभग 85 मील क्षेत्र का सीमांकन।

(II) उत्तरी त्रि-सन्धि स्थल (भारत-चीन-म्यामां) का निर्धारण।

(III) मणिपुर की काबाव घाटी में लगभग 20 मील लम्बी सीमा का सीमांकन

उपर्युक्त (I) और (II) के संबंध में प्रगति म्यांमां के इस रवैये के कारण रुकी पड़ी है कि उत्तरी त्रि-सन्धि स्थल हुंगन दर्रे के उत्तर में लगभग 85 कि०मी० लम्बी

पट्टी का सीमांकन कार्य भारत और चीन के बीच सीमा का मसला हल हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। (III) के संबंध में इस क्षेत्र में भारत और म्यामां के बीच पारम्परिक सीमा की व्याख्या पर कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं जो अभी भी अनसुलझी हैं।

3. अक्तूबर, 1993 में भारत के महापर्यवेक्षक की रंगून यात्रा और प्रत्युत्तर में जुलाई, 1994 में म्यामां के महापर्यवेक्षक की भारत यात्रा के बाद भारत-म्यामां सीमा पर लगे खम्बों के संयुक्त निरीक्षण, मरम्मत और रख-रखाव पर वार्षिक संयुक्त सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर, 1994 में आरंभ हुआ।

बंगलादेश

बंगला देश के साथ निपटान के लिए लम्बित पड़े मामलों में चकमा शरणार्थियों का प्रत्यावासन, बंगला देश से अवैध अप्रवास, विद्रोहियों से संबंधित गतिविधियों सीमांकन और परिवहन सम्पर्कों सहित सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग शामिल हैं।

2. बंगलादेश के साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा बंगलादेश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से नियमित उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखी गई है। इन यात्राओं के दौरान सभी बकाया मुद्दों के समाधान के लिए और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर काम करने के लिए सहमति हुई। फरक्का में गंगाजल के विभाजन पर दिसम्बर 1996 में बंगलादेश के प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने बंगला देश की चुनी हुई वस्तुओं पर, जिन्हें भारत में निर्यात किया जा सकता है, टेरिफ रियायतें देना मंजूर किया है।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मसलों में पाकिस्तानी जेलों में कैदी मछुआरों सहित भारतीयों को छुड़ाना और उनका प्रत्यावर्तन, भारत के विरूद्ध चलाए जा रहे आतंकवाद और तोड़फोड़ की गतिविधियों में पाकिस्तान द्वारा समर्थन, जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध मसले, सरक्रीक में सीमांकन और समुद्री सीमा का रेखांकन, व्यापारिक और आर्थिक मसले और दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा से संबंधित मसले शामिल हैं।

2. सरकार शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से भारत-पाकिस्तान के सभी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने द्विपक्षीय बातचीत व्यापक रूप से पुनः आरंभ करने की अपनी तत्परता की जानकारी पाकिस्तान को दे दी है। 28 से 31 मार्च, 1997 तक दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होगी।

चीन

1. हाल के वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में परिपक्वता और यथार्थता आई है। सीमांगत प्रश्न सहित बकाया मसलों को हल करने के साथ-साथ हमने सभी क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है।

2. दोनों पक्ष सीमा संबंधी प्रश्न के निष्पक्ष यथोचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के विषय में काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों पक्ष सीमा प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा में बातचीत कर रहे हैं। 1993 में सम्पन्न सीमा शांति, अनुरक्षण करार और नवम्बर, 1996 में सम्पन्न विश्वासोत्पदक उपाय से सम्बद्ध करार से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में योगदान मिलेगा।

चीन द्वारा हथिया लिया गया भू-भाग

1844. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 के युद्ध में चीन द्वारा हथियाये गये भू-भाग का क्षेत्रफल क्या है,

(ख) क्या चीन सिक्किम पर भारतीय सम्प्रभुता को स्वीकार करता है, और

(ग) क्या चीन अरूणाचल प्रदेश को अपने अधिकृत मानचित्र में चीनी भू-भाग के हिस्से के रुप में प्रदर्शित करता है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जम्मू और कश्मीर का लगभग 38 हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान "सीमा करार" के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5120 वर्ग कि० मी० भारतीय क्षेत्र चीन को अवैध रूप से सौंप दिया है।

(ख) और (ग) चीन की सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के एक बड़े भाग पर अपना दावा पेश किया है। उन्होंने सिक्किम को भारत के एक अंग के रूप में औपचारिक मान्यता भी दी है।